शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 49 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 49 अंक – 38 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 9 – 16 सितम्बर 2024 मूल्य पांच रूपये

प्रधानमंत्री द्वारा हिमाचल को चुनावी मुद्दा बनाना एक बड़ा संकेत है

- मंत्रियों के ब्यानों से उलझा मस्जिद विवाद पूरे प्रदेश में फैला
- जब शहर में चार – पांच हजार अवैध निर्माण है तो अकेले मस्जिद के खिलाफ कारवाई कैसे होगी
- जब 2010 से यह अवैधता चल रही थी तो क्या संबद्ध प्रशासन के खिलाफ भी कारवाई होगी?

शिमला/शैल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल की सुक्खू सरकार की स्थिति को लेकर जम्मू-कश्मीर और हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा है। मोदी ने आरोप लगाया है कि विधानसभा चुनावों के दौरान जनता की झूठी गारंटीयां देकर सता में आयी सरकार आज समय पर अपने कर्मचारियों को वेतन तक का भुगतान नहीं कर पा रही है। यह एक ऐसा आरोप है जिसका साक्ष्य सरकार के अपने ही फैसले बनते जा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री ने स्वयं यह मुद्दा उछाल दिया है तो निश्चित है कि आने वाले दिनों में भाजपा का हर नेता इस पर साक्ष्यों के साथ आक्रमक होगा। हिमाचल की कांग्रेस सरकार की इस परफारमैन्स का पड़ोसी राज्यों के चुनावों पर क्या असर पड़ेगा यह तो आने वाला समय ही बतायेगा। क्योंकि चुनावों में कई स्थानीय फैक्टर भी होते हैं जो मुद्दों पर भी भारी पड़ते हैं। लेकिन यह तय है कि प्रधानमंत्री का यह संज्ञान लेना प्रदेश की राजनीति को अवश्य प्रभावित करेगा और चुनावों में कांग्रेस की आक्रामकता पर भी भारी पड़ेगा। कांग्रेस पड़ोसी राज्यों में हिमाचल में कांग्रेस की सरकार होने का लाभ नहीं ले सकेगी। इस समय प्रदेश की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिये सरकार जो भी कदम उठा रही है उसका आम आदमी पर असर नकारात्मक ही पड रहा है। विपक्ष का हर नेता प्रदेश को कर्ज की इस दलदल में धकेलना का आरोप लगा रहा है। अनुराग ठाकुर ने तो सरकार पर तीस हजार करोड़ का कर्ज अब तक ले लेने पर सीधे कहा है कि अब तक की सरकारों ने जितना कर्ज लिया था उसका 50% तो इस सरकार ने दो वर्षो से कम समय में ही ले लिया है।

वित्तीय स्थिति के साथ ही मस्जिद विवाद को जिस तरह से सरकार ने हैंडल किया है उससे हालात और उलझ गये हैं। क्योंकि सरकार के मंत्रियों ने स्वयं स्वीकार लिया है कि अवैध निर्माण हुआ है। लेकिन मस्जिद के अवैध निर्माण को स्वीकारते हुये शहरी विकास मंत्री ने यहां यह भी खुलासा किया है कि शहर में चार-पांच हजार अवैध निर्माण है। स्वभाविक है कि

सारे अवैध निर्माणों पर एक सम्मान कारवाई करनी होगी। इसमें यह कठिन हो जायेगा की मस्जिद में अवैध निर्माण हुआ है इसलिए इसको तुरन्त गिरा दिया जाये। यह दूसरी बात है कि मुस्लिम समाज स्वत: ही इस निर्माण को गिराने के लिये तैयार हो जायें। लेकिन तब भी अन्य चार-पांच हजार अवैध निर्माण पर सरकार कब क्या कारवाई करती है इस पर जनता की नजर बनी रहेगी। इसी के साथ पंचायती राज मंत्री ने जिस तरह से सदन में खुलासा रखा है कि बांग्लादेशी और रोहिंगियां यहां पर आ गये हैं यह अपने में एक बड़ा तथ्य है। यह भी सदन में रखा गया कि कब से यह अवैध निर्माण चल रहा था। निगम प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाये गये हैं। जो कुछ मंत्री ने सदन में कहा है वही सब कुछ तो हिन्दू संगठन कह रहे हैं।

इस समय पूरे प्रदेश में यह मुद्दा फैल गया है क्योंकि अपरोक्ष में सरकार के दो मंत्रियों ने वह सब कुछ स्वीकार लिया है जो हिन्दूवादी संगठन कह रहे हैं। प्रदेश में कितनी मस्जिदें बन गयी हैं और कैसे बन गयी हैं क्या इसका जवाब सरकार से हटकर कोई दूसरी एजैन्सी दे सकती हैं? फिर सुक्खू सरकार को भी सत्ता में आये दो वर्ष होने जा रहे हैं। इस सरकार में यह खुलासे करने वाले भी पहले दिन से ही मंत्री हैं। तो क्या इन सब की भी बराबर की जिम्मेदारी नहीं बन जाती है। भाजपा ने तो अपने बूथ स्तर के नेताओं को भी इस मस्जिद मुद्दे पर कोई भी अधिकारिक टिप्पणी करने से रोक दिया है। अब यह मुद्दा पूरी तरह हिन्दू संगठनों के हाथ में चला गया है। मंत्रियों के ब्यानों ने उनके मुद्दे को प्रमाणिकता प्रदान कर दी है। यह ठीक है कि यह मुद्दा उलझने के बाद वित्तीय संकट की चर्चा पृष्ठभूमि में चली गयी है। लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा स्वयं इसको चुनावी चर्चा में लाना एक गंभीर संकेत है।

राज्यपाल ने 27वें राष्ट्रीय मशरूम मेले का शुभारंभ किया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने सोलन में 27वें राष्ट्रीय मशरूम मेले का शुभारंभ करते हुए कहा कि मशरूम की जीवन अवधि शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा

शोध करने की जरूरत है। मेले में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे राज्यपाल ने इस क्षेत्र को प्रोत्साहित करने और अधिक से अधिक लोगों को इसके साथ जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया।

मेले का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और मशरूम अनुसंधान निदेशालय सोलन द्वारा संयुक्त तौर पर किया जा रहा है। निदेशालय को बधाई देते हुए राज्यपाल ने कहा कि यह मेला वर्ष 1998 से लगातार हर वर्ष आयोजित किया जा रहा है। इसी दिन वर्ष 1997 में सोलन को मशरूम सिटी का नाम मिला। बीते 27 वर्षों में कई उत्पादकों ने मशरूम की खेती को रोजगार के तौर पर अपनाया है। उन्होंने कहा इस लंबे अरसे के दौरान मशरूम उत्पादकों ने मशरूम अनुसंधान निदेशालय सोलन की तकनीक के द्वारा विभिन्न प्रकार की किस्में विकसित की हैं।

राज्यपाल ने कहा कि वर्ष 1970 के अंत में भारत में मशरूम की खेती शुरू हुई और आज दुनिया के लगभग 100 देशों में इसकी खेती की जा रही है। भारत में जहां 10 वर्ष में मशरूम का उत्पादन एक लाख टन था वह आज 3.50 लाख टन पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि मशरूम उत्पादन में भारत चौथे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि मशरूम की खेती एक छोटे से कमरे से शुरू कर किसान दो तीन माह के भीतर आय अर्जित कर सकते हैं।

राज्यपाल ने कहा कि ग्रामीण युवाओं के लिए यह रोजगार का बहुत ही शानदार जरिया है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों, उत्पादकों, उद्यमियों और उद्योगों को एक मंच पर आकर मशरूम की पैदावार बढ़ाने के लिए प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि मशरूम अनुसंधान निदेशालय सोलन, भारत का एकमात्र संस्थान है जिसके देशभर में 32 मशरूम समन्वयक परियोजना केंद्र हैं। उन्होंने निदेशालय के वैज्ञानिकों से कहा कि वह कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से मशरूम की उत्पादन तकनीकों को देश के कोने-कोने तक पहुंचाएं ताकि नई किस्मों को बेहतर दाम मिलें और किसानों की आर्थिकी भी सुदृढ़ हो।

राज्यपाल ने कहा कि व्यावसायिक उत्पादन के अलावा जंगली मशरूम गुच्छी और कीड़ा-जड़ी मशरूम की ऐसी प्रजातियां हैं जिन पर शोध की आवश्यकता है। अगर गुच्छी और कीड़ा-जड़ी के उत्पादन वृद्धि होगी तो इसके अच्छे दाम मिल सकते हैं। उन्होंने किसानों को जागरूक करने के लिए समय-समय पर मेले, सेमिनार, प्रशिक्षण और प्रदर्शनियां आयोजित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

राज्यपाल ने असम के अनुज, महाराष्ट्र के गणेश, ओडिशा के प्रकाश चंद, बिहार की रेखा कुमारी और केरल के शिजे को प्रगतिशील मशरूम उत्पादक पुरस्कार से सम्मानित किया।

इससे पूर्व मशरूम अनुसंधान निदेशालय सोलन के निदेशक डॉ. वी. पी. शर्मा ने राज्यपाल का स्वागत किया और राष्ट्रीय मशरूम मेले, मशरूम उत्पादन और निदेशालय की उपलब्धियों से अवगत करवाया।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के बागवानी उप-महानिदेशक डॉ. संजय कुमार सिंह ने कहा कि निदेशालय ने मशरूम की नई किस्में विकसित की हैं और कई दुर्लभ किस्मों की वैश्विक स्तर पर भी काफी मांग है। उन्होंने कहा कि आज मशरूम का बहुत बड़ा बाजार है और इस मांग को पूरा करने के लिए आधुनिक पद्धतियों के साथ अधिक उत्पादन किया जाना चाहिए।

डॉ. यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन के कुलपति प्रो. राजेश्वर सिंह चंदेल भी कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से सफल उद्यमियों को विकसित करने में आईसीएआर-डीएमआर का बहुत बड़ा योगदान है।

इससे पूर्व, राज्यपाल ने विभिन्न उद्यमियों द्वारा मशरूम उत्पादन पर आधारित प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया। उन्होंने उद्यमियों से संवाद किया और उत्पादों में गहरी रूचि दिखाई।

राज्यपाल ने सरदार पटेल विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की

333 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान

विद्यार्थियों को राष्ट्र विकास में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने सरदार पटेल विश्वविद्यालय एसपीयू मंडी के पहले दीक्षांत समारोह में 333 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की। राज्यपाल इस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे तथा 12 स्वर्ण पदक विजेताओं सहित 36 मेधावी विद्यार्थियों को पदक

प्रदान किए।

विद्यार्थियों को बधाई देते हुए राज्यपाल ने विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनइपी 2020 के चरणबद्ध कार्यान्वयन, भारतीय ज्ञान परम्परा प्रकोष्ठ की स्थापना और विभिन्न शैक्षणिक समितियों के गठन के अलावा अल्पावधि में किए गए उल्लेखनीय कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह सभी पहल विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के प्रति विश्वविद्यालय के लक्ष्यों को पूरा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि यह समारोह केवल उपाधियां प्रदान करने तक सीमित नहीं है। यह विद्यार्थियों के लिए महत्त्वपूर्ण क्षण होता है जिससे उनके भविष्य को नई दिशा मिलती है। उन्होंने कहा कि भारत की शिक्षा प्रणाली बौद्धिक, नैतिक और अध्यात्मिक विकास पर आधारित है और एनइपी-2020 में उल्लेखित सिद्धांतो को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाती है और सभी को अपने ज्ञान को निरन्तर बढ़ाते रहना चाहिए।

राज्यपाल ने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि विश्वविद्यालय तथा यहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों का भविष्य सुनहरा होगा और आने वाले समय में यह विश्वविद्यालय देश के अग्रणी संस्थानों में से एक बनकर उभरेगा। भारत में युवाओं के लिए रोजगार के अपार अवसर हैं और देश की आबादी में से 55 प्रतिशत से अधिक युवा 25 वर्ष से कम के हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2030 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है और वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र का दर्जा हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने स्नातकों से न केवल अपनी सफलता के लिए बल्कि राष्ट्र व राज्य की प्रगति में भी योगदान देने का आग्रह किया।

आईआईटी रोपड़ के निदेशक राजीव आहुजा इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने विश्वविद्यालय की उन्नति में शोध की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। उन्होंने विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के लिए बहु-विषयक दृष्टिकोण अपनाने की वकालत की। उन्होंने भारत को वैश्विक गुरू बनाने के लिए उच्च-गुणवत्ता, शोध संचालित नवाचार की आवश्यकताओं को भी रेखांकित किया। उन्होंने कृषि प्रौद्योगिकी और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में कृत्रिम मेधा एआई और ड्रोन प्रौद्योगिकी को शामिल करने का भी आहवान किया।

विधायक एवं विश्वविद्यालय के कार्यकारी परिषद के सदस्य चन्द्रशेखर ने राज्यपाल का स्वागत करते हुए कहा कि यह दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। उन्होंने स्नातकों से देश और राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहते हुए वैश्विक चुनौतियों का सामना करने का आग्रह किया। उन्होंने विश्वविद्यालय को सरदार पटेल की 150 जयंती के अवसर पर वर्ष भर कार्यक्रम आयोजित करने को भी कहा।

विश्वविद्यालय के कुलपति ललित कुमार अवस्थी ने राज्यपाल का इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने राज्यपाल को विश्वविद्यालय की उपलब्धियों तथा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों से भी अवगत करवाया।

राज्यपाल के सचिव सी.पी. वर्मा, मंडलायुक्त राखी काहलो, उपायुक्त अपूर्व देवगन, पुलिस अधीक्षक साक्षी वर्मा, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर व कर्मचारियों सहित अन्य गणमान्य भी इस अवसर उपस्थित थे।

नौणी विवि के कुलपति को एनसीसी कर्नल की मानद रैंक से किया सम्मानित

शिमला/शैल। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी को डॉ. यशवंत सिंह परमार औदयानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के नौणी स्थित मुख्य परिसर में आयोजित पीपींग समारोह में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल को मानद कर्नल रैंक से सम्मानित किया।

इस अवसर पर जब मुख्य अतिथि एनसीसी शिमला के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर रोवीन ने प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल को कर्नल रैंक का बैज लगाया तो डॉ. एलएस नेगी सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कार्यक्रम का आयोजन 1 एचपी ब्वॉयज बटालियन सोलन द्वारा किया गया था।

प्रोफेसर चंदेल देशभर के उन 19 कुलपतियों की प्रतिष्ठित समूह का हिस्सा है, जिन्हें इस सम्मान से नवाजा गया है। प्रोफेसर चंदेल अब विश्वविद्यालय के एनसीसी विंग के कर्नल कमांडेंट की उपाधि धारण करेंगे। इस पहल का उद्देश्य कुलपतियों को उनके कार्यकाल के दौरान कर्नल कमांडेंट के रूप में नियुक्त करके विश्वविद्यालय परिसरों में एनसीसी के अनुशासन और देशभक्ति के लोकाचार को शामिल करना है। इस कार्यक्रम के तहत छात्रों में राष्ट्रीय कर्तव्य की भावना को बढ़ावा देकर सैन्य सेवा के प्रति उनके रुझान को मजबूत करना है।

अपने भाषण में प्रोफेसर चंदेल ने विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों के प्रति अपना गौरव और समर्पण व्यक्त किया। उन्होंने अनुशासन और नेतृत्व को बढ़ावा देने के एनसीसी के मिशन का समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। प्रोफेसर चंदेल, जो स्वयं एक पूर्व एनसीसी कैडेट और एनसीसी बी सर्टिफिकेट धारक हैं ने इस अवसर पर एनसीसी का आभार व्यद्र किया। उन्होंने नेरी और थुनाग में अपने घटक कॉलेजों में एनसीसी इकाइयां स्थापित करने की विश्वविद्यालय प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने युवाओं को अनुशासन प्रदान करने और उन्हें सैन्य करियर के लिए तैयार करने में एनसीसी की भूमिका की सराहना की और उन्होंने निस्वार्थ सेवा के लिए रक्षा कर्मियों की सराहना की।

ब्रिगेडियर रोवीन ने प्रोफेसर चंदेल को मानद कर्नल रैंक से सम्मानित करने पर बधाई दी और हिमालय क्षेत्र में छोटे और सीमांत किसानों के लिए कम लागत, पर्यावरण के अनुकूल कृषि पद्धतियों को आगे बढ़ाने और परिसर में एनसीसी गतिविधियों को बढ़ावा देने में उनके काम की सराहना की। उन्होंने छात्रों को कड़ी मेहनत और समर्पण के माध्यम से सच्चा नेतृत्व अपनाने, दूसरों में अच्छाई देखने और अपने समय का सही उपयोग करने और नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए किताबें पढ़ने में अपना समय निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया।

समारोह का समापन विश्वविद्यालय के एनसीसी कैडेटों द्वारा कुलपति को गार्ड ऑफ ऑनर देकर किया गया। 1

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादकःजे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

मुख्यमंत्री ने सीता राम येचुरी के निधन पर किया शोक व्यक्त

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सीपीआई एम के महासचिव एवं पूर्व सांसद सीता राम येचुरी के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। सीता राम येचुरी का लंबी बीमारी के बाद दिल्ली में निधन हो गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी के उत्थान के लिए सीता राम येचुरी का योगदान अतुलनीय है और लोग उन्हें लंबे समय तक याद रखेंगे।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा शोक संतप्त परिवारजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है।

बागवानी नीति लागू करने वाला पहला राज्य होगा हिमाचल: मुख्यमंत्री

82,500 लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तरीके से मिलेंगे रोजगार के अवसर

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बागवानी विभाग की एचपी शिवा परियोजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश देश में बागवानी

नीति लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा। इसका उद्देश्य राज्य में बागवानी उत्पादन को बढ़ाना और प्रदेश को फल राज्य बनाना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 1,292 करोड़ रुपये की यह परियोजना राज्य के सात जिलों में 6 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करेगी। उन्होंने अंतर-फसलीय खेती पर बल देते हुए कहा कि दो चरणों में अमरूद, नींबू प्रजाति के फलों, अनार, ड्रैगन फ्रूट, जामुन तथा कटहल के पौधे रोपे जाएंगे।

उन्होंने विभाग को निर्देश दिए कि परियोजना में छोटे तथा सीमांत किसानों को शामिल किया जाए ताकि उनकी आर्थिकी सुदृढ़ हो सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है तथा बागवानी क्षेत्र किसानों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सुक्खू ने कहा कि परियोजना के तहत वर्ष 2028 तक छः हजार हेक्टेयर भूमि में 60 लाख फलों के पौधे रोपे जाएंगे। परियोजना के तहत प्रथम चरण में चार हजार हेक्टेयर भूमि तथा दूसरे चरण में शेष दो हजार हेक्टेयर भूमि को कवर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से वर्ष 2032 तक 1.30 लाख मीट्रिक टन उत्पादन होने की उम्मीद जताई, जिसका प्रतिवर्ष लगभग 230 करोड़ रुपये का व्यापार मूल्य होगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से राज्य के 82,500 लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तरीके से रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।

मुख्यमंत्री ने विभाग को निर्देश दिए कि इस परियोजना में सूचना प्रौद्योगिकी और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाए ताकि किसानों को उनकी फसलों के बेहतर दाम मिल सकें। उन्होंने कहा कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही 70 प्रतिशत आबादी विभिन्न कृषि गतिविधियों से जुड़ी है। उन्होंने विभाग को इस परियोजना को सफल बनाने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता व सहयोग प्रदान करने के निर्देश दिए।

बैठक में सचिव बागवानी प्रियंका बसु, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, निदेशक बागवानी विनय सिंह तथा राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से मिले न्यू डवेलपमेंट बैंक के प्रतिनिधि

शिमला/शैल। शिमला शहर में 1734.40 करोड़ रुपये से बनने वाले रज्जू मार्ग के संबंध में उप-मुख्यमंत्री मुकेश

अग्निहोत्री से न्यू डवेलपमेंट बैंक के तीन सदस्यीय दल ने भेंट की। यह दल शिमला, धर्मशाला और मनाली में गत 10 सितम्बर से पांच दिवसीय फैक्ट फांइडिंग मिशन पर हिमाचल में है। इस मिशन की शिमला नवाचार शहरी परियोजना के लिए ऋण प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका है।

उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला में दुनिया का दूसरा, भारत और एशिया का पहला 15 स्टेशनों को जोड़ने वाले 13.79 किलोमीटर लम्बे रज्जू मार्ग का निर्माण कार्य पहली मार्च, 2025 से आरम्भ होगा और इसे चार वर्ष के भीतर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि शिमला में ट्रैफिक की समस्या के स्थाई समाधान, स्थानीय लोगों एवं पर्यटकों को यातायात की सुलभ सुविधा प्रदान करने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में यह परियोजना मील पत्थर साबित होगी।

मुकेश अग्निहोत्री ने दल के प्रतिनिधि टोनी नकूना, गर्वित शाह और चरमेन काजामूला से मुलाकात के दौरान यह आश्वस्त किया कि ऋण से जुड़ी सभी आवश्यक औपचारिकताओं को राज्य सरकार पूरा करेगी ताकि न्यू डवेल्पमेंट बैंक केन्द्र के आर्थिक कार्य विभाग के साथ ऋण संबंधी औपचारिकताओं को निर्धारित समयावधि में पूरा कर सके।

उन्होंने कहा कि रज्जू मार्ग के निर्माण के लिए भूमि की आवश्यकता सहित अन्य सभी औपचारिकताओं को प्रदेश सरकार शीघ्र पूरा करेगी और इसके निर्माण को लेकर निविदाएं दिसम्बर, 2024 तक आमंत्रित की जाएंगी।

समग्र जल विद्युत क्षमता में सर्वोच्च उपलब्धि हासिल करने के लिए हिमाचल को मिला पुरस्कार

शिमला/शैल। जल विद्युत क्षमता में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए हिमाचल प्रदेश को वैश्विक अक्षय ऊर्जा

निवेशक सम्मेलन एवं एक्सपो में समग्र जल विद्युत क्षमता में सर्वोच्च उपलब्धि हासिल करने वाले राज्य से सम्मानित किया गया। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने गुजरात के गांधीनगर में आयोजित वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन एवं एक्सपो में हिमाचल प्रदेश को प्रमाण-पत्र प्रदान किया। राज्य सरकार की ओर से मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर और विधायक नीरज नैयर ने यह पुरस्कार प्राप्त किया।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इस उपलब्धि पर बधाई देते कहा कि वर्तमान सरकार हिमाचल प्रदेश को 31 मार्च 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए कारगर कदम उठा रही है और इसके लिए सरकार ने अब तक कई पहल भी की हैं।

उन्होंने कहा कि जल विद्युत और नवीनीकरण ऊर्जा का दोहन करने के लिए सरकार विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड छः माह के भीतर पेखूबेला स्थित 32 मेगावाट के सोलर प्लांट का संचालन शुरू कर दिया गया है। वहीं, दो सौर ऊर्जा परियोजनाओं, 10 मेगावाट की कुटलैहड़ और पांच मेगावट की भांजल परियोजना को भी जल्द जनता को समर्पित किया जाएगा।

उन्होंने कहा इन परियोजनाओं के शुरू होने से जहां कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, वहीं जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता भी कम होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित कर रही है। सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर डीजल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से बाहर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार हरित उद्योगों को बढ़ावा दे रही है।

उन्होंने सरकार पर भरोसा जताने के लिए प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि लोगों के दृढ़ सहयोग के कारण राज्य सरकार सफलतापूर्वक विभिन्न नीतियां एवं कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों के परिणामस्वरूप आगामी कुछ वर्षों में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य के रूप में विकसित होगा।

विभागीय परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 सितम्बर से 19 अक्तूबर तक

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा बोर्ड के एक प्रवक्ता ने बताया कि विभागीय परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 20 सितम्बर से 19 अक्तूबर, 2024 तक मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से आरम्भ की जाएगी।

उन्होंने कहा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, भारतीय वन सेवा और हिमाचल प्रदेश वन सेवा, हिमाचल में कार्यरत अन्य सभी राजपत्रित एवं पात्र अराजपत्रित अधिकारी अधीक्षक वर्ग-2 और वरिष्ठ सहायक तकनीकी व गैर तकनीकी, आबकारी एवं कराधान विभाग के आबकारी और कराधान निरीक्षक, परिवहन विभाग के अधिकारी व पात्र कर्मचारी, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अधिकारी व पात्र कर्मचारी, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के अभियन्ता अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य पर्यटन विभाग के सहायक अभियन्ता, राजस्व विभाग के पटवारियों के लिए विभागीय परीक्षाएं 26 नवम्बर, 2024 से 05 दिसम्बर, 2024 तक आयोजित की जाएंगी।

पेपर नम्बर एक 'वित्तीय प्रशासन' में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की सुविधा के लिए इस परीक्षा का आयोजन बोर्ड द्वारा मण्डी तथा धर्मशाला केन्द्रों में भी किया जाएगा।

परीक्षा से जुड़ी अधिक जानकारी हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान (हिप्पा) की वेबसाइट www.hipashimla.nic.in पर उपलब्ध करवा दी गई है।

लोक निर्माण मंत्री ने सड़क निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए

शिमला/शैल। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को खराब प्रदर्शन करने

वाले ठेकेदारों के विरूद्ध कड़ी कारवाई अमल में लाने के निर्देश दिए।

उन्होंने प्रमुख परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विभाग द्वारा की गई उल्लेखनीय प्रगति के लिए विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान अब तक रखरखाव कार्य में 526.42 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है। विभाग ने बुनियादी ढांचे के विकास में उल्लेखनीय प्रगति की है और इस वर्ष 18 पुलों, 33 भवनों, 190.44 किलोमीटर मोटर योग्य सड़कों और 309.22 किलोमीटर क्रॉस ड्रेनेज का निर्माण किया गया है। इसके अलावा 674.30 किलोमीटर सड़कों पर तारकोल बिछाया गया है और 1060 किलोमीटर सड़कों का समय समय पर नवीनीकरण किया गया है।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-2 के तहत शत-प्रतिशत तथा पीएमजीएसवाई-1 के अंतर्गत 99 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में प्रदेश में नाबार्ड के तहत 337 परियोजनाएं चल रही हैं, जबकि शेष 15 परियोजनाओं को शीघ्र आवंटित कर दिया जाएगा।

मंत्री ने बताया कि लोक निर्माण विभाग का डिजिटलीकरण किया जा रहा है, जिसके लिए विभाग के डब्ल्यूएएमआईएस साफ्टवेयर को अपग्रेड करने पर सक्रिय रूप से कार्य किया जा रहा है। यह कदम पीडब्ल्यूडी की कार्य प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा और परियोजना निष्पादन में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। यह साफ्टवेयर निविदा प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा और कार्यों को समय पर पूरा करने और सुशासन में दक्षता और जवाबदेही पर सरकार की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करेगा।

विक्रमादित्य सिंह ने अधिकारियों को ठेकेदारों के कार्यों की निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्धारित समय और गुणवत्तापूर्ण काम न करने वाले ठेकेदारों के विरूद्ध कारवाई कर उन्हें ब्लैक लिस्ट करने को कहा। उन्होंने उच्च गुणवत्ता मानकों को पूरा करने वाले ठेकेदारों को और कार्य देकर पुरस्कृत करने की सिफारिश भी की।

विक्रमादित्य सिंह ने भारी बारिश से हुए नुकसान पर चर्चा करते हुए लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों द्वारा किए गए बहाली कार्यों की सराहना की। उन्होंने विभाग को क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों की तत्काल मरम्मत और रखरखाव को प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए ताकि जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

मस्तिष्क की शक्तियां सूर्य की किरणों के समान हैं। जब वो केन्द्रित होती हैं, चमक उठती हैं।

..... स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

क्या प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक राजनीतिक परिदृश्य बदल पायेगा

इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा को अकेले अपने ही दम पर सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं मिल पाना एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना है। मोदी सरकार सहयोगियों के सहारे पर आश्रित है। इसलिए यह कहना कठिन है कि यह सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पायेगी या नहीं। क्योंकि नरेन्द्र मोदी अपने पहले दोनों कार्यकालों में जिस तरह से सरकार चलाते रहे हैं उसे सामने रखकर यह तय है कि बैसाखियों के सहारे ज्यादा देर तक चलना मोदी के स्वभाव में नहीं है। फिर जिन बैसाखियों के सहारे मोदी सरकार है उन पर भी यहां भरोसा कर पाना संभव नहीं है कि वह भी अन्त तक सरकार को बिना शर्त सहयोग देते रहेंगे। इन चुनावों में जिस तरह से भाजपा अध्यक्ष ने आरएसएस को लेकर ब्यान दिया है उससे भी यही संकेत उभरता है कि शायद यह सरकार अपना कार्यकाल पूरा न कर पाये। नरेन्द्र मोदी और सरकार के चाणक्य अमित शाह लोकसभा में भाजपा को बहुमत में लाने के लिये सहयोगी और अन्य छोटे दलों के विलय की योजना पर काम करें। राज्यसभा में यह खेल शुरू भी हो चुका है। लेकिन इस तरह के खेल के लिये जनता में एक अनुकूल वातावरण का होना आवश्यक है। जिसमें जनता स्वंय मांग करने लग जाये कि छोटे दलों को बड़े दलों में विलय हो जाना चाहिये। इस बार राम मन्दिर निर्माण के बाद यहां कतई नहीं लग रहा था कि भाजपा को अपने दम पर बहुमत नहीं मिलेगा। क्योंकि कांग्रेस राजस्थान और छत्तीसगढ़ अपनी सरकारें होने के बावजूद हार चुकी थी। इसलिए कांग्रेस को बड़ी चुनौती नहीं माना जा रहा था। लेकिन फिर भी लोकसभा में कांग्रेस का अपने दम पर नेता प्रतिपक्ष का पद हासिल करना भी उतनी ही बड़ी घटना है जितनी भाजपा का बहुमत न पाना है।

इस राजनीतिक परिदृश्य में फिर यह स्थिति निर्मित हो गई है कि क्या कांग्रेस मोदी बीजेपी का विकल्प बन पायेगी? इसके लिये यह स्वभाविक है कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें है उनकी परफॉरमैन्स की तुलना की जायेगी। आज हिमाचल में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद प्रदेश की चारों लोकसभा सीटें यह सरकार हार गयी। यह ठीक है कि विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस अपनी सरकार बचाने में सफल रही है। लेकिन इस सफलता के बावजूद वस्तुस्थिति यह बन गयी है कि यदि किन्हीं कारणों से प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो जायें तो कांग्रेस को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि खराब वित्तीय स्थिति के कारण वेतन भत्ते विलंबित करने की जानकारी मुख्यमंत्री स्वयं विधानसभा में लिखित में रख चुके हैं। प्रधानमंत्री ने प्रदेश सरकार की इस परफॉरमैन्स को राज्यों के चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाकर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। प्रधानमंत्री के इस हमले से कांग्रेस की विश्वसनीयता पर निश्चित रूप से गंभीर प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। इसी के साथ हिमाचल सरकार में जिस तरह से मस्जिद विवाद को हैंडल किया है उससे भी कांग्रेस पर गंभीर सवाल खड़े हो गये हैं। कुल मिलाकर हिमाचल की कांग्रेस सरकार की परफॉरमैन्स से स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस अभी मोदी भाजपा का विश्वसनीय विकल्प नहीं बन पा रही है। हिमाचल जैसे प्रदेश में एक अवैध निर्माण के आरोपों पर पूरे राज्य में हिन्दू संगठनों के लिये विरोध प्रदर्शनों का मुद्दा बन जाना किसी गणित से सरकार की सफलता का मानक नहीं बन सकता।

इसी परिदृश्य में आये वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को केन्द्र सरकार की एक बड़ी रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। केन्द्र सरकार का यह प्रस्तावित संशोधन लोकसभा में अपनों और परायों के विरोध के परिणाम स्वरूप प्रवर समिति को जा चुका है। लेकिन इससे आम जनमानस में यही सन्देश गया है कि इस संशोधन के माध्यम से सरकार वक्फ संपत्तियों को सरकार के अधीन लाना चाहती है ताकि उनका शैक्षणिक, स्वास्थ्य संस्थान और अन्य सामाजिक कार्यो के लिये उपयोग कर सके। सामान्य समझ के मुताबिक यह एक अच्छा प्रयास है इसका विरोध किया जाना गलत है। इसमें कौन आदमी को समझायेगा की वक्फ का अर्थ क्या है? कैसे उसके पास संपत्तियां आती हैं। इस प्रस्तावित संशोधन के प्रवर समिति को जाने के बाद देश की विभिन्न अदालतों में इसके पक्ष में सौ से अधिक याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। राज्यसभा में एक प्राइवेट सदस्य का प्रस्ताव विचार के लिये अनुमोदित हो चुका है। इस तरह वक्फ संशोधन विधेयक पूरे देश में चर्चा के केन्द्र में आ गया है। न चाहते हुये भी एक हिन्दू बनाम मुस्लिम बहस चल पड़ी है जिसका राजनीतिक प्रतिफल बहुत दूरगामी होगा। इस मुद्दे पर फिर से चुनाव में जाने के विकल्प पर यदि मोदी आ जाते हैं तो आम आदमी इसका विरोध नहीं कर पायेगा। ऐसे मुद्दे पर चुनाव में जाने से मोदी दूसरों के सहारे सरकार बनाने की बाध्यता से बच जायेंगे। क्योंकि कांग्रेस अभी अपनी राज्य सरकारों के कारण विकल्प होने तक नहीं पहुंच सकी है।

देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का सही वक्त आ गया है

गौतम चौधरी

भारत ने विभिन्न बाहरी सांस्कृतिक आक्रमण और धार्मिक आवरणों की तकलीफ को झेलने के बावजूद अपने हजार साला इतिहास, संस्कार, आचार व विचार, परंपरा और ज्ञान की अविरल धारा को विपरीत परिस्थितियों में भी संजो कर रखे हुए है। ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि भारत की संस्कृति सार्वभौमिक, समावेशी, सार्वदेशिक व सार्वकालिक है।

भारतीय विचारधारा की बुनियाद वसुधैव वुटुम्बकम् पर आधारित है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सन्ने सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कदि् दुख भागभवेत पर आरूढ़ है। यह केवल एक मंत्र मात्र नहीं अपितु हर हिन्दुस्तानी इस पर दृढ़ता से विश्वास करते हैं और वास्तव में इसका पालन भी करता है। शायद यही वजह रही जिसने इकबाल को यह लिखने के लिए मजबूर किया। ''यूनान-ओ-मिस्त्र-ओ-रूमा, सब मिट गए जहां से अब तक मगर है बाकी, नाम-ओ-निशां हमारा, वुछ बात है कि हस्ती, मिटती नहीं हमारी सदियों रहा है दुश्मन, दौर-ए-जमां हमारा।'' इन्हीं खूबियों की वजह से आज हम सारे जहां में अतुलनीय और लाजवाब हैं। जहां सभी देश और धर्म अपने आप को श्रेष्ठ और अन्य को निम्नतर होने का दावा करते हैं, वहीं भारत ने ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का उद्घोष किया और पहली बार इस विचार को जन्म दिया कि जिस तरह हम अच्छे हैं उसी तरह आप भी अच्छे हैं। दुनिया के मान्यता प्राप्त 195 देशों में भारत एक मात्र ऐसा देश है जहां लगभग केवल हर धर्म के अनुयायी ही नहीं अपितु उसके उप-धर्म व पंथों के अनुयायी भी पूरी धार्मिक और सामाजिक आजादी के साथ जिन्दगी गुजारते हैं। जिस धर्म को किसी भी देश ने जगह नहीं दिया, उस को भी भारत ने सम्मानपूर्वक फलने-पूलने का समान अवसर प्रदान किया है। हम इस कारण सेक्युलर नहीं हैं कि हमारा संविधान सेक्युलर है, बल्कि हमारा सनातनी विचार न केवल मनुष्यों का अत्यधिक सम्मान करना सिखाता है बल्कि इस पृथ्वी पर ईश्वर द्वारा रचित सभी प्राणियों से स्नेह भाव रखने की प्रेरणा देता है। सभी धर्मो और पंथों का आदर करना हमारे सांस्कृतिक डीएनए में सम्मिलित है और ये सभी गुण भारत के संविधान में भली भांति प्रतिबिबित हुए हैं।

यह धारणा कि हम अनेक से एक हुए हैं न केवल आधारहीन बल्कि भ्रमित करने वाला भी है। हम एक से अनेक हुए हैं। जिस प्रकार एक दरख्त में उसकी शाखाएं होती हैं, उसके पत्ते होते हैं, उसके टहनीयां होती हैं, उसके फल और पूल होते हैं ठीक उसी प्रकार भारत में रहने वाले सभी सनातनी थे सभी सनातनी हैं और इनशाल्लाह सनातनी ही रहेंगे। हां उनकी धार्मिक मान्यताएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं पर संस्कृति और पारंपरिक चिंतन उसका एक है। इबादत और पूजा पद्धति अलग हो सकती है लेकिन उसके सोचने का ढंग एक ही होगा। कोई सनातनी मुसलमान हो सकता है, कोई सनातनी ईसाई हो सकता है, कोई सनातनी सिख हो सकता है और कोई सनातनी यहूदी हो सकता है। क्योंकि यह माटी हमें एक-दूसरे से बांटना सिखाती ही नहीं है।

इसकी आजादी और जमानत हमारे देश का संविधान देता है। मगर वोट की राजनीति करने वाले और कुछ बाहरी शक्तियों के बहकावे में आने वालों ने इस देश के मुस्लिम कौम को धर्म के जंजाल में इस तरह फंसा कर रख दिया है कि मुसलमान अपनी ही या अपने ही इतिहास, अपने ही परंपरा, अपने ही संस्कार और अपने ही रीति नियम से दूर होते जा रहे हैं। दुर्भाग्य से यह स्थिति केवल भारत में ही देखने को मिलती है। ईरानी, इोनेशियाई, मलेशियाई और अरब इस्लाम के अनुयायी होने के बावजूद भी अपने पूर्व इस्लामी इतिहास, परंपरा और संस्कृति को नहीं भुले। यहां तक कि अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के भी कुछ मुसलमान अपनी जड़ों की ओर लौटने की कोशिश करने लगे हैं।

संभवतः भारत के मुसलमान नए-नए इस्लाम में परिवर्तित हुए थे और यह साबित करना चाहते थे कि वे अरब और ईरानी से बेहतर मुसलमान हैं इसलिए भारतीय मुसलमानों ने अपने ही तहजीब और तमद्दुन से अलग होना प्रारंभ किया। यही कारण है कि आज भारतीय मुसलमान टोइजम के शिकार हैं। चूंकि भारतीय मुसलमान कम पढ़े-लिखे हैं इसलिए आसानी से गुमराह होते रहे हैं। भारतीय मुसलमानों कों मुस्लिम और मोमिन में फर्क करना होगा। शरीअत का इल्म नहीं। भारतीय मुसलमानों ने कुरान शरीफ पढ़ा ही नहीं, अगर पढ़ा है तो समझा नहीं और समझा है तो उसपर अमल किया नहीं किया। होवूक अल एबाद और होवूक अल्लाह का फलसफा पता नहीं। इसलिए आसानी से गुमराह होते रहे हैं। समान नागरिक संहिता के संदर्भ मे भी यही हो रहा है।

मुसलमानों को यह कहकर भ्रमित किया जा रहा है कि आम नागरिक कानून उनकी धार्मिक गतिविधियों में भारी बदलाव लाएगा। इससे उनकी नमाज और रोजा जैसी धार्मिक प्रथाओं में वुछ बदलाव होंगे। यह इस्लाम के पांच स्तंभों में प्रवेश करके हिदू कानून लागू करेगा, जो निति रूप से निराधार और झूठा प्रचार है। सामान्य नागरिक कानून कभी भी किसी भी धार्मिक प्रथाओं की धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसकी गारंटी संविधान की धारा 25 और 26 देता है। यह कानून केवल विवाह, तलाक, गोद लेने और विरासत से संबंधित है। नीचे कुछ ऐसी बात दी जा रही है जिसे जानकर कोई भी इस कानून के समर्थन में उतर सकता है।

शरीयत बनता है, कुरान से, हदीस से, इज्मा और कियास से। जिन कानूनी प्रावधानों की चर्चा कुरान शरीफ में नहीं है इसका वर्णन हदीस द्वारा किया गया है। यदि कोई प्रावधान हदीसों में वर्णित नहीं है तो इसका निर्णय इस्लामी विद्वानों के बीच व्यापक परामर्श के बाद लिया जाता है। यदि इस्लामी विद्वान आम सहमति तक पहुंचने में विफल रहते हैं तो अनुमान लगाया जाता है कि कुरान और हदीस के अमुक शब्द या लेखन का यह तात्पर्य हो सकता है। यह इज्मा का ही परिणाम है कि आज इस्लामी न्यायशास्त्र में 5 विचारधाराएं, हन्फी, शाफेई, मालेकी, हॅम्बली और जाफरी विकसित हुई हैं और इनके बीच विवाह, तलाक, रखरखाव, विरासत और गोद लेने के संबंध में बहुत सारे मतभेद पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कोई मुसलमान नशे में होने के बावजूद अपनी पत्नी को तलाक दे देता है तो हन्फी मजहब के अनुसार तलाक हो जाएगा लेकिन इस्लाम का अन्य फिरका इसे तलाक नहीं मानता हैं। एक पत्नी जो हन्फी मजहब की मानने वाली है अगर उसका पति अनियत काल से लापता है, तो उसको उस अवधि तक प्रतीक्षा करनी होगी जब उसकी उम्र के लोगों का निधन हो जाए। अर्थात जब उसकी उम्र 90 वर्ष के आसपास हो। हालांकि शाफेई, मालेकी, हंबली मजहब के अनुसार ऐसी पत्नी को 4 साल तक ही प्रतीक्षा करनी होगी। समान नागरिक कानून लागू हो जाने से हनफी-मालेकी, हम्बली-शाफेई मजहब के बीच जो मतभेद हैं, समाप्त हो जाएंगे।

यह कानून सभी शहरियों को कानून के एक धागा में पिरोने का काम करेगा। वोटबैंक की सियासत को खत्म करने में मददगार साबित होगा। इस से महिलाओं को समान अधिकार मिलेगा और उनकी स्थिति में भी सुधार आएगा, जिस प्रकार फौजदारी के सभी धराएं तमाम नागरिकों पर समान रूप से लागू है ठीक इसी तरह दीवानी की धराएं भी सभी पर समान रूप से लागू होंगी, जिस से भेद-भाव समाप्त होगा।

इस्लामी शरीयत के मुताबिक इंसान के ऊपर दो प्रकार के हुवूक हैं। पहला हुवूक खुदा का होता है जैसे उसपर यकीन करना और उस के साथ किसी को शरीक न मानना। उसके द्वारा भेजे गए सभी दूतों पर विश्वास करना और उनकी आज्ञाओं का पालन करना। नमाज, रोजा, हज, जकात आदि का खालिस नियत के साथ सख्ती से पालन करना। इस हुवूक को हुवुक अल अल्लाह कहते हैं। दूसरा हुवूक इंसान का इन्सान के ऊपर होता है जिसे हुवूक अल एबाद मानव अधिकार कहते हैं। विद्वानों के अनुसार इस्लामिक धार्मिक किताबों में खुद सर्वशक्तिमान परमात्मा ने कहा है कि अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को साक्षी न ठहराओ और माता-पिता के साथ भलाई करो और रिश्तेदारों, यतीमों, मुहताजों, नजदीकी पड़ोसियों, दूर के पड़ोसियों, अपने साथी, मुसाफिर और उन लोगों के साथ, जिनके पास तुम्हारे दाहिने हाथ हों। निस्संदेह, अल्लाह उन लोगों को पसन्द नहीं करता जो आत्म-भ्रम करते हैं और भ्रम करते हैं। इसके अतिरिक्त मानव जाति के प्रति सहानुभूति, जानवरों को कष्ट न पहुंचाना, एकत्र होने का शिष्टाचार, बातचीत का शिष्टाचार, मिलने का शिष्टाचार आदि हुवूक अल एबाद में शामिल हैं। इस्लाम में हुवूक अल एबाद हुवुक अल अल्लाह से श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि यह मानव का मानव के साथ होने वाला व्यवहार है। सामान्य नागरिक संहिता इस मायने भी बेहतर है। अतः इसका खुले मन और दिल से स्वागत होना चाहिए।

जब एक देश एक ध्वज, एक आधार कार्ड, एक राशन कार्ड, एक पाठय पुस्तक, एक स्थायी खाता संख्या, एक फौजदारी आईन हो सकता है तो एक सामान्य नागरिक संहिता क्यों नहीं? हां इसमें एक बात का ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए। शासन को समान नागरिक संहिता लागू करने से पहले मसौदा तैयार करने के लिए सभी धर्मो के न्यायशास्त्र विशेषज्ञ और कानून विशेषज्ञ की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाना चाहिए। सामान्य नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करते समय संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 को ध्यान में रखा जाना चाहिए। क्योंकि यह समय की मांग है। सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लाने का यह सबसे अच्छा समय है। अनुच्छेद 14 के महत्व को समझते हुए पूरे देश में एक अनुवूल माहौल बनाया जाना चाहिए। सामान्य नागरिक संहिता में धर्मो और समुदाय के सवरेत्तम, वैज्ञानिक और उत्कृष्ट व्यक्तिगत कानून को शामिल करने के लिए ईमानदार प्रयास भी जरूरी है। एक बात यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इस मामले में शासन या सरकार को मौकापरस्त पार्टियां, या फिर अन्य बाहरी शक्तियों से प्रभावित विद्वानों की तरह राजनितिक लाभ के लिए नहीं देश व समाज हित के लिए इसे लागू करना चाहिए।

नौणी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में रोजगार, जलवायु परिवर्तन और स्थिरता पर प्राकृतिक खेती के प्रभाव पर डाला प्रकाश

शिमला। सतत टिकाऊ खाद्य प्रणालियों को को सक्षम बनाने के लिए प्राकृतिक खेती विषय पर डॉ. यशवंत

सिंह परमार औदयानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी द्वारा आयोजित दो दिवसीय आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन विभिन्न सिफारिशों के साथ संपन्न हुआ। राष्ट्रीय कृषि, खाद्य और पर्यावरण अनुसंधान संस्थान (INRAE) और भारतीय पारिस्थितिकी सोसायटी के हिमाचल चैप्टर के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में भारत, फ्रांस, सर्बिया, यूके, मॉरीशस, उज़्बेकिस्तान और नेपाल के वैज्ञानिक, किसान और उद्योग के पेशेवर एक साथ एक मंच पर प्राकृतिक कृषि जैसे पर्यावरण हितैषी कृषि पद्धतियों पर विचार विमर्श करने के लिए एक मंच पर आये।

उत्तराखंड बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भडसार के कुलपति डॉ. परविंदर कौशल समापन सत्र में कुलपति रहे। डॉ. कौशल ने पोषण सुरक्षा के लिए प्राकृतिक खेती के महत्व और इस पर्यावरण-अनुकूल कृषि पद्धति को बढ़ावा देने में शिक्षा और उद्योग की भूमिका पर जोर दिया। नौणी विवि के कुलपति प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल ने प्राकृतिक खेती के लिए एक स्थायी खाद्य प्रणाली मंच विकसित करने में विश्वविद्यालय के प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और मिट्टी, वायु और पानी के स्वास्थ्य को बढ़ाने में प्राकृतिक खेती के लाभों को रेखांकित किया, जो बदले में उपभोक्ता स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालता है।

फ्रांस की लिसिस लैब की उप निदेशक प्रोफेसर एलीसन लोकोन्टो ने एक्रोपिक्स परियोजना से अंतर्दृष्टि साझा की और आशा व्यक्त की कि भारत सहित विभिन्न देशों की स्थायी प्रथाओं को विश्व स्तर पर दोहराया जा सकता है। आईसीएआर के अतिरिक्त महानिदेशक डॉ. राजबीर सिंह ने जलवायु परिवर्तन को कम करने में प्राकृतिक खेती की क्षमता पर जोर दिया और देश के 732 कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए आईसीएआर की पहल के बारे में विस्तार से बताया।

टिकाऊ खाद्य प्रणालियों में नवाचारों पर चर्चा ने एकीकृत कृषि प्रणालियों को बढ़ाने में आईओटी प्रौद्योगिकी और फार्म टाइपोलॉजी ढांचे की भूमिका को रेखांकित किया। ये प्रौद्योगिकियाँ भूमि विखंडन और जलवायु भेद्यता जैसी चुनौतियों का स्थायी समाधान प्रदान करती हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा, लचीलापन और कृषि उत्पादकता में सुधार होता है।

पैनल चर्चाओं में कीटनाशक मुक्त कृषि प्रणाली प्राप्त करने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता पर आम सहमति सामने आई। विशेषज्ञों ने बताया कि इस लक्ष्य के लिए विविध हितधारकों को शामिल करते हुए नवीन अनुसंधान और प्रणालीगत परिवर्तन दोनों महत्वपूर्ण हैं।

सतत खाद्य प्रणालियों में नवाचार सत्र के दौरान चर्चा की गई ASIRPA TR विधि को एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण के रूप में उजागर किया गया था जो लक्ष्यों को स्पष्ट करता है, साझेदारी को परिष्कृत करता है और प्रभावशाली परिवर्तन के लिए सक्रिय रणनीतियों को बढ़ावा देता है।

कृषि पारिस्थितिकी प्रथाओं को बेहतर बनाने में शिक्षा जगत, उद्योग और किसानों की भूमिकाओं पर एक पैनल चर्चा में कई प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया। डॉ. मनीष कुमार, डीन सीओएच नौणी ने स्थानीय फसल विविधता और पारंपरिक ज्ञान को पहचानने के महत्व पर जोर दिया। सिंजेंटा के डॉ. यशवंत पाटिल ने जैव-उत्तेजक, जैव-उर्वरक और जैव-कवकनाशी विकसित करने में उद्योग की भूमिका पर चर्चा की। प्राकृतिक कृषि तंत्र एलएलपी, पुणे के सुजीत कुमार चक्रवर्ती ने कृषि पंचांग को कृषि पाठयक्रम में एकीकृत करने की वकालत की। खेती विरासत मिशन पंजाब के उमेंद्र दत्त ने चावल और गेहूं की फसलों से परे व्यापक खाद्य सुरक्षा संवाद की आवश्यकता पर बल दिया। प्रगतिशील सेब उत्पादक जित्तू चौहान और किसान जीवन सिंह राणा ने नए किसानों को प्रशिक्षण देने में ऑनलाइन शिक्षा और सफल किसान भागीदारी के महत्व पर प्रकाश डाला। डीडीजी शिक्षा डॉ. आरसी अग्रवाल ने छात्र-किसान जुड़ाव बढ़ाने के लिए मोबाइल एप्लिकेशन-आधारित RAWE कार्यक्रमों को एकीकृत करने का आहवान किया।

सम्मेलन का समापन खाद्य जीविका और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए प्राकृतिक खेती में नवाचारों को आगे बढ़ाने पर एक पैनल चर्चा के साथ हुआ। CIRAD, फ्रांस के वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉ. ब्रूनो डोरिन ने आंध्र प्रदेश के भविष्य के परिदृश्यों पर अंतर्दृष्टि प्रस्तुत की। सिफारिशों में भोजन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार करने, 5 मिलियन किसानों के लिए रोजगार पैदा करने और बेरोजगारी को 30% से 7% तक कम करने के लिए प्राकृतिक खेती की क्षमता के बारे में बात की गई। जतन ट्रस्ट के डॉ. कपिल शाह ने कृषि इनपुट के आधार पर उपज को मापने की आवश्यकता पर जोर दिया, जबकि सेंट औबिन ग्रुप, मॉरीशस के डॉ. अलीज़ी गुइम्ब्यू ने मॉरीशस में कीटनाशकों के उपयोग को कम करने के लिए शैक्षिक पहल का आहवान किया।

डॉ. राकेश शर्मा ने सभी सत्रों की सिफ़ारिशें जबकि डॉ. सुधीर वर्मा ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस अवसर पर निदेशक अनुसंधान डॉ. संजीव चौहान, निदेशक विस्तार शिक्षा डॉ. इंदर देव और डॉ. प्रदीप कुमार भी मौजूद रहे। सम्मेलन ने प्राकृतिक कृषि पद्धतियों में सार्थक प्रगति के लिए मंच तैयार किया, जिससे बढ़ी हुई स्थिरता, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण प्रबंधन का मार्ग प्रशस्त हुआ।

यूनिवर्सल कार्टन सेब बागवानी के लिए महत्वपूर्ण पहल

यूनिवर्सल कार्टन के माध्यम से बागवानों ने 1 करोड़ 11 लाख 92 हजार से अधिक पेटी सेब मंडियों में भेजा

शिमला। यूनिवर्सल कार्टन की व्यवस्था प्रदेश में सेब बागवानी के क्षेत्र में बहुआयामी प्रयास है जिससे बागवानों के उत्पाद की गुणवत्ता की सुरक्षा के साथ उन्हें बेहतर दाम प्राप्त करने में मदद मिल रही है। सरकार के इस कदम से बागवानों को नई दिशा व आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद जगी है।

प्रदेश में बागवानों को पैकिंग समाधान की आवश्यकता और सेब की गुणवत्ता को बनाए रखने व बेहतर दामों की आवश्यकता के तहत यूनिवर्सल कार्टन की उपयोगिता कारगर साबित हो रही है। पारम्परिक कार्टन के उपयोग से फसलों को नुकसान की शंका व कीमतें गिरने की समस्या से भी निजात मिलेगी। यूनिवर्सल कार्टन से बागवानों को मानकीकृत, टिकाऊ और उच्च गुणवत्ता वाली पैकिंग सुविधा प्राप्त हुई है जिससे फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई व बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। इससे सेब को होने वाली क्षति से बचाया जा सकता है व गुणवत्ता बनी रहती है।

इससे जहां बागवानों को सेब की कीमत तय करने का अधिकार मिला है वहीं बिचौलियों और व्यापारियों की निर्भरता से बागवान का बचाव होगा। यूनिवर्सल कार्टन के माध्यम से बागवान सीधे अपने उत्पाद की पैकिंग बेहतर रूप से करके अधिक मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए विशेष मानक भी निर्धारित किए गए हैं जिसमें आकार, तहों की संख्या, वजन अथवा क्षमता आदि मानकों का पालन कर उच्च गुणवत्ता वाले कार्टनों के माध्यम से फलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है।

प्रदेश सरकार द्वारा इसे लागू करने के लिए बागवानों का समर्थन, कार्टन की उपलब्धता, प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था के माध्यम से कार्टन का सही उपयोग करने के प्रति जानकारी व जागरूकता प्रदान की गई। स्थानीय स्तर पर कार्टन निर्माण इकाइयों को प्रोत्साहित कर बागवानों को कार्टन उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास किया।

बागवानों की आय में वृद्धि तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए यूनिवर्सल कार्टन महत्त्वपूर्ण कदम है। अन्य फसलों के लिए भी ये पहल एक आदर्श के रूप में देखा जा रही है।

इस वर्ष सेब सीजन के दौरान प्रदेश में लगभग 1 करोड़ 11 लाख 92 हजार 542 यूनिवर्सल कार्टन से सेब की फसल अभी तक देश की विभिन्न मंडियों में पहुंचाई जा चुकी है। हिमाचल प्रदेश में कृषि उत्पाद विपणन समिति के अन्तर्गत मंडियों द्वारा तथा समितियों के माध्यम से स्थापित नियंत्रण कक्षों एपीएमसी में मंडियों के बाहर से जाने वाले माल के पंजीकरण के तहत अभी तक शिमला एवं किन्नौर समिति में 71 लाख 48 हजार 757, सोलन से 19 लाख 47 हजार 511, कुल्लू एवं लाहौल-स्पिति कृषि उत्पाद विपणन समिति द्वारा 13 लाख 1668 यूनिवर्सल कार्टन के माध्यम से सेब देश की मंडियों में भेजा गया। कांगड़ा विपणन समिति से 5,201, सिरमौर 1312, ऊना समिति द्वारा 918, बिलासपुर 456 तथा हमीरपुर के माध्यम से 1921 व चम्बा कृषि उत्पाद विपणन समिति द्वारा 30 पेटी यूनिवर्सल कार्टन का कारोबार भी किया गया। एचपीएमसी द्वारा भी लगभग 50 हजार यूनिवर्सल कार्टन प्रदेश की विभिन्न मंडियों में भेजे गए हैं।

सुख-आश्रय योजना:करसोग के 41 लाभार्थियों को मिली 10 लाख रुपए की पॉकेट मनी

शिमला। राज्य सरकार की महत्वकांक्षी मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना से ग्रामीण व दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले पात्र लाभार्थी लाभान्वित होने लगे हैं। इस योजना का लाभ करसोग क्षेत्र के चिन्हित लाभार्थियों को भी मिलना शुरू हो गया है। क्षेत्र के सभी चिन्हित 41 लाभार्थियों को राज्य सरकार की ओर से प्रतिमाह 4 हजार रुपये की राशि पॉकेट मनी के रूप में प्रदान की जा रही है। गौरतलब है कि योजना में 0 से 27 वर्ष के आयु वर्ग के ऐसे अनाथ बच्चों को शामिल किया गया है, जिनका पालन-पोषण करने वाला अपना कोई नहीं है। राज्य सरकार द्वारा इन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट घोषित किया गया है।

योजना के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को राज्य सरकार द्वारा अप्रैल, 2024 से सितंबर, 2024 तक 6 माह की पॉकेट मनी 24 हजार रुपए प्रति लाभार्थी प्रदान की गई है। चयनित सभी 41 लाभार्थियों को लगभग 10 लाख रुपए की राशि लाभार्थियों को प्रदान की गई है। इन सभी लाभार्थियों को राज्य सरकार द्वारा सुख-आश्रय योजना के अंतर्गत लाकर चिल्ड्रन अ फ द स्टेट के रूप में अपनाया गया है और सभी के जीवन-यापन का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के दिशा-निर्देशानुसार एक वृहद योजना तैयार कर पात्र बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है।

राज्य सरकार की महत्वकांक्षी सुख-आश्रय योजना के दायरे में मंडी जिला में लगभग 400 लाभार्थियों को इस योजना में शामिल कर, लाभान्वित किया जा रहा है। मंडी जिला में योजना के अंतर्गत चयनित सभी लाभार्थियों को लगभग 94 लाख 72 हजार रुपए की आर्थिक सहायता पॉकेट मनी के रूप में प्रदान की गई है। चौंतड़ा ब्लॉक में 39, धर्मपुर में 32, द्रंग में 55, गोहर में 26, गोपालपुर में 51, रिवालसर में 34, सदर में 55, सराज में 35, सुंदरनगर में 32, करसोग में 41 लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया गया है।

सीडीपीओ करसोग विपाशा भाटिया ने बताया कि राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं ताकि पात्र लोगों को योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके। सुख-आश्रय योजना के लिए क्षेत्र के चिन्हित सभी पात्र लाभार्थियों को इस योजना के अन्तर्गत 24-24 हजार रुपये की पॉकेट मनी जारी कर दी गई है।

संपत्ति जब्त करने का प्रावधान बनाने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्यः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि अवैध और नकली शराब के मामलों में लोगों, उनके रिश्तेदारों और सहयोगियों की संपत्ति को जब्त करने की अनुमति देता है।

संपत्ति जब्त करने का प्रावधान बनाने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि अवैध और नकली शराब बनाने के धंधे में संलिप्त लोगों पर लगाम कसने के लिए प्रदेश सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है।

उन्होंने कहा कि हाल ही में राज्य विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 2011 में संशोधन कर इस तरह की गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल लोगों पर नकेल कसने के लिए यह प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण संशोधन अवैध गतिविधियों में शामिल श्री सुक्खू ने कहा कि इससे पहले अधिनियम में इस तरह का कोई प्रवधान नहीं था। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश इस प्रावधान को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। इसके अलावा, इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए, इन अपराधों को अब संज्ञेय और गैर-जमानती बना दिया गया है।

उन्होंने कहा कि नए प्रावधान अवैध शराब के धंधे जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करने में बहुत मददगार साबित होंगे। उन्होंने कहा कि संशोधनों में अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत जुर्माने में वृद्धि और सजा की अवधि को भी बढ़ाया गया है।

उन्होंने कहा कि नाबालिगों को शराब बेचना और शराब बेचने के लिए उनका इस्तेमाल करना बहुत गंभीर मसला है। इसके समाधान के लिए नए कानून में अब अपराधियों को दंड और जुर्माना दोनों का प्रावधान किया गया है। अपराधियों को छह माह जेल की सजा और 50 हजार तक का जुर्माना किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि इन प्रावधानों को प्रभावशाली तरीके से लागू करने के लिए प्रवर्तन एजेसियों को सशक्त किया जा रहा है। इस तरह के मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए आबकारी पुलिस फोर्स के गठन का भी प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने मंडी में वर्ष 2022 में हुई घटना को दोहराया जहां नकली शराब पीने से आठ लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी।

मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि नकली शराब के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर पूरी सख्ती बरती जाएगी ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में मादक पदार्थो की तस्करी और इस्तेमाल से निपटने के लिए भी कई कदम उठा रही है।

राज्य सरकार 1200 से अधिक पुलिस कर्मियों की भर्ती कर रही है जिसका मुख्य उद्देश्य इस तरह की गतिविधियों से निपटना होगा।

राज्य सरकार ने आबकारी एवं कराधान विभाग का पुनर्गठन किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने आबकारी एवं कराधान विभाग का पुनर्गठन किया है जिसके तहत वस्तु एवं सेवा कर विंग और आबकारी विंग बनाए गए हैं। विभागीय कार्यो को सुव्यवस्थित करने और लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से यह पहल की गई है।

उन्होंने कहा कि अलग विंग बनाने का निर्णय काफी समय से लंबित था, विशेषकर जुलाई 2017 से जब जीएसटी अधिनियम लागू किया गया था। वर्तमान राज्य सरकार ने इसकी आवश्यकता को महसूस करते हुए यह पहल की है। उन्होंने कहा कि विभाग की कार्यकुशलता और कार्यप्रणाली में सुधार के लिए अलग-अलग विंग बनाने की बहुत आवश्यकता थी।

उन्होंने कहा कि विभिन्न कानूनी संरचनाओं और नियामक आवश्यकताओं को देखते हुए, तकनीकी, कानूनी और नियामक पहलुओं पर विशेष प्रशिक्षण बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करने और जनता को अधिक प्रभावी ढंग से सुविधा प्रदान करने में मदद करेगा। इससे कार्यभार का समान बंटवारा और सुदृढ़ क्षेत्रीय संचालन भी सुनिश्चित होगा।

सुक्खू ने कहा कि प्रत्येक विंग में विशेषज्ञों के होने से, अधिकारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में केंद्रित विशेषज्ञता विकसित करने से कार्यकुशलता में सुधार आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर अधिकारी करदाता सेवाओं और राजस्व निगरानी पर ध्यान केंद्रित करेंगे जबकि आबकारी विंग अपने संचालन के सामाजिक प्रभाव को देखते हुए नियामक कार्यो को संभालेगा।

उन्होंने कहा कि अभी अधिकारियों पर कई तरह के कार्यो का बोझ है जिससे कार्यप्रणाली प्रभावित हो सकती है। उन्होंने कहा कि विभाग के पुनर्गठन से जिम्मेदारियों का स्पष्ट विभाजन होगा जिससे इस मुद्दे को हल करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि विभाग के पुनर्गठन के तहत 38 नए पद सृजित किए जाएंगे। पुनर्गठन के बाद कॉमन पूल में 87 कर्मचारी होंगे, जबकि वस्तु एवं सेवा कर विंग में 718 और एक्साइज विंग में 632 कर्मचारी होंगे।

सुक्खू ने कहा कि पड़ोसी राज्यों जम्मू-कश्मीर, पंजाब और उत्तराखंड ने पहले ही अपने आबकारी व कराधान विभागों को अलग-अलग शाखाओं में पुनर्गठित कर दिया है और अब प्रदेश भी उसी राह पर आगे बढ़ा है। उन्होंने कहा कि पुनर्गठन से प्रत्येक शाखा में अधिक केंद्रित दृष्टिकोण सुनिश्चित होगा, जिससे पूरे राज्य में सार्वजनिक सेवाओं और नियामक कार्यो में बढ़ोतरी होगी।

उप-मुख्यमंत्री ने थुनाग में जल शक्ति विभाग के तहत 7.65 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया शिलान्यास

सराज क्षेत्र में जल शक्ति विभाग के माध्यम से विकास कार्यो पर व्यय किए जा रहे 144 करोड़ रुपए:मुकेश अग्निहोत्री

शिमला/शैल। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सराज विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत लम्बाथाच एवं रोड के लिए 4.41 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से निर्मित होने वाली उठाऊ सिंचाई योजना हलीन व बलैण्ढा का शिलान्यास किया। उन्होंने ज्वाल खड्ड व बगस्याड नाला के

बाढ़ नियंत्रण कार्य का भी शिलान्यास किया, जिस पर लगभग 3.24 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे।

इस अवसर पर मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार सभी क्षेत्रों के समान विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि हलीन व बलेंढा योजनाएं डेढ़ वर्ष में जबकि बाढ़ नियंत्रण कार्य आगामी एक वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सराज विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति विभाग के थुनाग मंडल के माध्यम से वर्तमान में लगभग 144 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। क्षेत्र में 57 करोड़ 59 लाख रुपए की 16 पेयजल योजनाएं तथा लगभग 59 करोड़ 33 लाख रुपए की 10 सिंचाई योजनाएं चल रही हैं। इसके अतिरिक्त नाबार्ड तथा एसडीएमएफ के तहत बाढ़ नियंत्रण कार्यो पर 15.11 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जंजैहली एवं थुनाग में मल निकासी योजनाओं पर लगभग 12.30 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। इसे अतिरिक्त थुनाग मंडल के तहत करसोग क्षेत्र में भी दो पेयजल योजनाओं पर 11.18 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जा रही है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत सराज क्षेत्र में लगभग 34 हजार नल लगाए गए हैं।

उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आज वे नेता प्रतिपक्ष के गृह क्षेत्र में आये हैं और यहां भी विकास कार्यो की गति कम नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले कार्यकाल में वे नेता प्रतिपक्ष रहे और उस समय भाजपा सरकार को सत्ताच्युत करने का संकल्प लिया और इसे पूरा भी किया। यही हमारे लोकतंत्र की खूबी है। लोकसभा चुनावों में 400 पार का नारा 240 तक सिमट गया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विरोध नीतियों एवं विचारधारा तक ही सीमित रहना चाहिए, इसी सोच के साथ वर्तमान प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रहने वाले सभी लोगों में आपसी भाईचारा व सद्भावना बनी रहनी चाहिए। हाल ही में हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कानून के दायरे में रहकर ही कार्य करेंगे।

उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के ध्येय से कार्य कर रही प्रदेश सरकार ने सहकारी विभाग का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण करने का निर्णय लिया है। इससे सहकारिता क्षेत्र में होने वाली धांधलियों पर रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल सहकारिता आंदोलन का जनक रहा है और यहां बैंकिंग, बुनकर, दुग्ध उत्पादन, परिवहन, शिक्षा तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रों में सहकारी समितियां उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं। प्रदेश सरकार हर स्तर पर सहकारिता गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है।

इस अवसर पर मिल्क फैडरेशन के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रदेश कांग्रेस समिति के महासचिव चेतराम ठाकुर ने उप-मुख्यमंत्री का स्वागत किया और इन विकास कार्यो के शिलान्यास के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने क्षेत्र की विभिन्न मांगों से भी उन्हें अवगत करवाया। कांग्रेस बुद्धिजीवी सेल के अध्यक्ष विजय पाल सिंह ने भी जनसभा को संबोधित किया।

इस अवसर पर उपाध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश्वर चौहान, महासचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी व हिमाचल पथ परिवहन निगम के निदेशक धर्मेंद्र धामी, महासचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी व प्रभारी सराज विधानसभा क्षेत्र रमेश चौहान, विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारी व अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

आर.एस.बाली ने एचडीएफसी बैंक की शाखा विस्तारीकरण का शुभारम्भ किया

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम अध्यक्ष आर. एस. बाली ने छोटा शिमला स्थित एचडीएफसी बैंक की शाखा विस्तारीकरण का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शाखा विस्तारीकरण से लोगों को बेहतर व सुलभ बैंकिंग सेवाएं मिल पाएंगी। उन्होंने शाखा के विस्तारीकरण पर बैंक प्रबन्धन को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्हें पूर्ण आशा है कि प्रदेशवासियों की आर्थिक

उन्नति और वित्तीय समावेशन में शाखा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस अवसर पर कांगड़ा के पूर्व विधायक सुरेन्द्र काकू, एचडीएफसी बैंक के हिमाचल सर्कल हैड नीरज कौरा, शाखा प्रबन्धक मुरली मेहता सहित बैंक के अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

निदेशक आयुष ने राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की

बोर्ड के सभी कार्यो को पूर्णतः डिजिटलाइज किया जाएगा

शिमला/शैल। निदेशक आयुष निपुण जिन्दल ने हिमाचल प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हिमाचल राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी बोर्ड के नियम भारतीय राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति आयोग के अनुसार बनाए जाने का निर्णय लिया गया है और बोर्ड द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सकों और फार्मासिस्टों के पंजीकरण शुल्क में कोई भी बढ़ोतरी न करने की सिफारिश भी की गई है।

उन्होंने कहा कि बोर्ड के सभी कार्यो को पूर्णतः डिजिटलाइज करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में प्रदेश के प्राइवेट प्रैक्टीशनर की चिकित्सा दक्षता के लिए जिला स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने को स्वीकृति प्रदान की गई।

निदेशक ने बताया कि बोर्ड द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सक व आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की सुविधा के लिए hpayushboard.org पोर्टल स्थापित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से वह पंजीकरण तथा पंजीकरण समाप्ति पर नवीनीकरण, सर्टिफिकेट डाउनलोड, पता बदलने, अनापत्ति प्रमाणपत्र तथा पंजीकरण रद्द करवा सकते हैं।

बैठक में वित्त वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान आय-व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत कर पारित किया गया। निदेशक आयुष ने कहा कि ब्यौरे की रिपोर्ट प्रदेश सरकार को शीघ्र सौंपी जाएगी।

प्राकृतिक खेती में हिमाचल प्रदेश अन्य राज्यों का कर रहा है मार्गदर्शनः राज्यपाल

प्राकृतिक खेती पर नौणी विश्वविद्यालय में अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के किसान प्राकृतिक खेती पद्धति को अपनाने में गहरी रूचि ले रहे हैं और यह खुशी की बात है कि खेती की इस पद्धति को अपनाने में अन्य राज्य भी आगे आ रहे हैं।

राज्यपाल जिला सोलन के डॉ. वाईएस परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी में प्राकृतिक खेती के अन्तर्गत सतत् खाद्य प्रणालियों को सक्षम बनाने में विषय पर आयोजित दो दिवसीय अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत बतौर मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे।

राज्यपाल ने देशभर में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा प्रदान करने के लिए नौणी विश्वविद्यालय की प्रशंसा की। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में आचार्य देवव्रत की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में हिमाचल देश का अग्रणी राज्य है और प्रदेश में किसानों ने सफलतापूर्वक प्राकृतिक खेती पद्धति को अपनाया है। राज्य में प्राकृतिक खेती की सफलता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि राज्य में 3584 ग्राम पंचायतों के 1.94 किसान 34 हजार 342 हैक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती से विविध फसलों की पैदावार कर रहे हैं।

राज्यपाल ने कहा कि नीति आयोग ने देश में प्राकृतिक खेती के क्रियान्वयन के लिए हिमाचल प्रदेश के म डल पर आधारित प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन की शुरूआत की है। हिमाचल जैसे छोटे राज्य के लिए यह गौरव की बात है कि देश के कृषि विज्ञानी, शोधकर्ता, पर्यटक, किसान और कृषि अधिकारी प्राकृतिक खेती की विस्तृत जानकारी हासिल करने के लिए हिमाचल के खेतों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्राकृतिक खेती के महत्त्व से भली-भांति परिचित है इसलिए इस पद्धति को बढ़ावा प्रदान किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने भारतीय प्राकृतिक खेती पद्धति को पारम्परिक कृषि विकास योजना से जोड़ा है और इसके सफल क्रियान्वयन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

राज्यपाल ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में प्रदेश की प्रत्येक पंचायत से 10 किसानों को जोड़कर प्रदेश के 36 हजार किसानों को इस पद्धति से जोड़ा जाएगा और उन्हें पोर्टल के माध्यम से प्राकृतिक खेती का प्रमाणीकरण दिया जाएगा। प्राकृतिक खेती से पैदा हुए उत्पादों का बेहतर विपणन सुनिश्चित करने के लिए 10 नए कृषक उत्पादक संघ गठित किए जाएंगे।

गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने हिमाचल प्रदेश के किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए बधाई दी और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नौणी विश्वविद्यालय के विज्ञानियों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने इस दिशा में विभिन्न विश्वविद्यालयों के शोध कार्यो के सकारात्मक परिणामों की जानकारी देते हुए कहा कि भविष्य के लिए कृषि की यह पद्धति अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने वैश्विक उष्मीकरण के दुष्प्रभावों और कृषि उत्पादों की पैदावार बढ़ाने के लिए यूरिया और टीएपी के अत्याधिक उपयोग से होने वाले नुकसानों के बारे में भी विस्तारपूर्वक जानकारी दी।

इससे पूर्व कुलपति डॉ. राजेश्वर सिंह चंदेल ने कहा कि आचार्य देवव्रत ने हिमाचल में प्राकृतिक खेती अभियान को शुरू किया था। उन्होंने कृषि विभाग को प्रदेश में इस अभियान का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित करने में दिए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के डॉ. आर सी अग्रवाल ने कहा कि परिषद् प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में अनुसंधान और इससे संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा प्रदान करने में हर संभव सहायता प्रदान कर रही है।

ए ल आ ई ए स आ ई ए स, आईएनआरएई, फ्रांस के उपनिदेशक प्रोफेसर एलीसन एम लोकोंटो ने नौणी विश्वविद्यालय को अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करने के लिए बधाई देते हुए कहा कि आईएनआरएई कृषि, कृषि उत्पादों के विपणन, प्रमाणिकरण और कृषि आधारित रासायनों के उपयोग को कम करने की दिशा में कार्य कर रहा है।

इंडियन इकोलोजिकल सोसाइटी हिमाचल चैप्टर के अध्यक्ष डॉ. प्रदीप कुमार ने कहा कि प्रदेश के किसान बढ़चढ़ प्राकृतिक खेती की पद्धति को अपना रहे हैं।

शिक्षा एवं समन्वयक आयोजन समिति के डायरेक्टर एक्सटेंशन डॉ. इन्द्र देव ने राज्यपाल और अध्यक्ष का स्वागत किया। आयोजक समिति के डॉ. एसके चौहान ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

राज्यपाल के सचिव सीपी वर्मा, सोलन के उपायुक्त मनमोहन शर्मा, पद्म श्री डॉ. नेकराम और विद्यानंद सरैक, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति और प्रगतिशील किसान इस अवसर पर उपस्थित रहे।

विक्रमादित्य सिंह ने किया सराज टेलेन्ट एवं टूरिज्म फेस्टिवल चौलूथाच (जंजैहली) का शुभारम्भ

शिमला/शैल। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने तीन दिवसीय सराज टेलेन्ट एवं टूरिज्म फैस्टिवल चौलूथाच जंजैहली का शुभारम्भ किया। उन्होंने जिला स्तरीय नलबाड़ मेला लम्बाथाच का समापन किया और जंजैहली के क्लब महेंद्रा

होटल में स्वास्थ्य एवम परिवार कल्याण विभाग द्वारा एचडीएफसी बैंक और क्लब महेंद्रा के आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप का शुभारंभ किया।

उन्होंने सराज टेलेन्ट एवं टूरिज्म फैस्टिवल चौलूथाच जंजैहली का शुभारम्भ करते हुए कहा कि सराज विधानसभा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अलग पॉलिसी का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने इस मेले के सफल आयोजन के लिए 51 हजार रुपये देने की घोषणा की।

इस फैस्टिवल का आयोजन विधानसभा में पर्यटन को मजबूत करने के लिए सिविक सैंस सोसायटी द्वारा किया जा रहा है। फैस्टिवल में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ सराज विधानसभा के टेलेंट को उभारने का प्रयास होगा। इस उत्सव का आयोजन वर्ष 2016 में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने शुरू किया था परन्तु कोरोना और अन्य कारणों से पिछले कुछ सालों से इसका आयोजन नहीं हो रहा था। अब इसे पुनः शुरू किया गया है।

लोक निर्माण मंत्री ने मेले के शुभारम्भ अवसर पर कहा कि सनारली से शंकरदेहरा रायगढ़ सड़क का निर्माण 13 करोड रुपये की लागत से चल रहा है। बरसात के बाद इस सड़क की मेटलिंग और टायरिंग का कार्य शुरू कर दिया जाएगा और अगले वर्ष जून माह तक इसका निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही 10 करोड़ रुपये की लागत से बनाई जा रही बगस्याड-राही धार-कथयाली-धनवाड-शिकारी माता मन्दिर सड़क और 13 करोड़ रुपये की लागत से बनाई जा रही पटीकरी-बाड़ा-शील-कशमीलीधार सड़क का निर्माण भी अगले वर्ष जून माह में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 71 करोड़ रुपये की लागत से बनाए जा रहे संयुक्त कार्यालय भवन जंजैहली, ग्रामीण आजीविका केन्द्र बजेही, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र थूनाग और गड़ागुशैणी का निर्माण भी जून, 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यों पर समय पर निपटाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बिना गिफट डीड के बनाई गई सड़कों के भूमि मालिकों द्वारा मुआवजे के कोर्ट जाने पर सरकार पर बोझ पड़ रहा है। इस कारण से अब यह निर्णय लिया गया है कि जब तक सड़क के लिए भूमि विभाग के नाम नहीं होगी तब तक सड़क का निर्माण नहीं किया जाएगा।

उन्होंने सराज के लोगों से पर्यटन के विकास के लिए प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना परम्परागत वास्तुकला के आधार पर ही भवनों का निर्माण करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पर्यटक यहां की खूबसूरती देखने आते हैं इसलिए यहां की प्राकृतिक खूबसूरती बरकरार रहे। उन्होंने कहा कि पर्यटक के विकास से यहां के लोगों को स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव चेत राम ठाकुर ने बताया कि सराज को पर्यटन के मानचित्र पर उभारने की शुरूआत हो चुकी है। इस वर्ष डेढ लाख लोग शिकारी मन्दिर में दर्शन करने के लिए आए। इससे इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिला है। उन्होंने स्थानीय लोगों से आग्रह किया कि वह कानून का पालन करें और यहां आने वाले पर्यटक का शानदार आतिथ्य सतकार करें ताकि यहां आने वाले पर्यटक सराज की सुनहरी यादें लेकर जाए। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने इस क्षेत्र को सड़कों से जोड़ा है। इस विधानसभा में 3 महाविद्यालयों खोले। उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पुनः शुरू किए गए इस महोत्सव को सिराज के अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर भी आयोजित किया जाएगा ताकि पर्यटन की दृष्टि से अनछुए क्षेत्रों को भी पर्यटन मानचित्र पर उभारा जा सके।

अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में पहली बार होगा सम्मिश्रण सांस्कृतिक कार्यक्रम

शिमला/शैल। मुख्य संसदीय सचिव एवं जिला स्तरीय अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा आयोजन समिति के अध्यक्ष सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि इस बार 13 से 19 अक्तूबर, 2024 तक अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार यह प्रयास किए जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा देशों की इसमें सहभागिता हो। इस बार एक विशेष सम्मिश्रण सांस्कृतिक कार्यक्रम भी

आयोजित किया जाएगा, जिसमें भारतीय और विदेशी संस्कृति का मिश्रण प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर वर्ष की भांति अंतरराष्ट्रीय नृत्य महोत्सव इस आयोजन का मुख्य आकर्षण है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के रंगारंग लोक नृत्यों के साथ-साथ विभिन्न देशों की संस्कृति को भी प्रदर्शित किया जाएगा।

यह बात ठाकुर ने नई दिल्ली स्थित हिमाचल सदन में आयोजित '30 डेज टू गो' उद्घाटन समारोह (Curtain Raiser Ceremony) को संबोधित करते हुए कही। मुख्य संसदीय सचिव ने 17वीं शताब्दी से चली आ रही कुल्लू दशहरा की ऐतिहासिक परंपरा की झलक दिखाई। उन्होंने कहा कि कुल्लू में लगभग 365 स्थानीय देवी-देवता निवास करते हैं इसलिए इस भूमि को देवभूमि के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के आयोजन के लिए अब तक 332 स्थानीय देवी-देवताओं को निमंत्रण भेजा जा चुका है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इस कार्यक्रम को बड़े स्तर पर आयोजित करने के निर्देश दिए हैं इसलिए न केवल कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार करने के प्रयास किए जा रहे हैं, बल्कि इसके विस्तार पर भी विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सात दिवसीय यह कार्यक्रम बीते वर्षों की परंपरा के अनुसार मनाया जाएगा, हालांकि वाणिज्यिक व्यापार मेले दीवाली के त्योहार तक जारी रहेंगे। इसमें ऑटो मेला, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय और विभिन्न अन्य संगठनों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी और स्टॉल शामिल हैं।

मुख्य संसदीय सचिव ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कुल्लू दशहरा के बारे में लोगों को व्यापक स्तर पर जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन भारी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है जहां वे हस्तशिल्प, ऊनी वस्त्र आदि उत्कृष्ट वस्तुएं भी खरीद सकते हैं।

ठाकुर ने देशभर के लोगों का कुल्लू में इस भव्य आयोजन को देखने के लिए आने का अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि रथ यात्रा, सांस्कृतिक परेड, कुल्लू कार्निवाल, ललहरी, खेल गतिविधियां, कला केंद्र प्रदर्शन और व्यापार मेला सात दिवसीय इस आयोजन के मुख्य आकर्षण होंगे। इस अवसर पर उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा विवरणिका का विमोचन भी किया।

प्रधान आवासीय आयुक्त एस. के. सिंगला ने आयोजन के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

मस्जिद निर्माण में कांग्रेस के मंत्रियों का भाजपा पर आरोप कोविड महामारी के दौरान बनाया गया विवादित ढांचा

- भाजपा सरकार ने मस्जिद निर्माण के लिए लाखों रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की:अनिरुद्ध सिंह
- नगर निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भूमिका पर उठाये सवाल:विक्रमादित्य सिंह

शिमला/शैल। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने संजौली स्थित मस्जिद में बिना अनुमति बनाए गए ढांचे को गिराने को लेकर हिन्दू जागरण मंच सहित दक्षिणपंथियों द्वारा किए गए आन्दोलन पर पत्रकार वार्ता में कहा कि हिमाचल में धार्मिक सद्भाव एवं आन्तरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए संजौली मस्जिद के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ और वक्फ बोर्ड के सदस्य मौलवी शहजाद सहित मन्दिर समिति के अन्य सदस्यों ने नगर निगम शिमला के आयुक्त को चिट्ठी के माध्यम से आयुक्त कार्यालय द्वारा मस्जिद को सीलबंद करने के लिए सहमति जाहिर की है। इसके अलावा चिट्ठी में उन्होंने आयुक्त से आग्रह किया है कि यदि नगर निगम की अनुमति मिले तो वह गैर–कानूनी तरीके से बनाए गए मस्जिद के ढांचे को स्वयं तोड़ने के लिए तैयार हैं।

उन्होंने कहा कि हिमाचल एक शांतिप्रिय राज्य है और इस सद्भाव को बिगाड़ते हुए प्रदेश में किसी को भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सदैव ही शांति एवं भाईचारे का प्रतीक रहा है लेकिन संजौली विवाद में कुछ साम्प्रायिक ताकतों ने इस छवि को बिगाड़ने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि यह विवादित ढांचा कोविड महामारी के दौरान खड़ा किया गया था और उस समय प्रदेश में भाजपा की सरकार थी।

अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि भाजपा सरकार के समय मस्जिद के अधिकारियों को योजना शीर्षक–वीकेवी/2019/774 के तहत 2 लाख रुपये प्रदान किए गए थे। उन्होंने यह भी बताया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान मस्जिद के लिए लाखों रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार शीघ्र ही रेहड़ी–फड़ी लगाने के लिए नीति लाएगी। प्रवासियों के प्रदेश आने पर उनकी जांच पड़ताल सही ढंग से हो इसके लिए मुख्यमंत्री एवं विधानसभा के अध्यक्ष मिलकर एक नए संस्थान को बनाने पर विमर्श करेंगे। इसके अलावा किराए पर रह रहे लोगों, दुकानों में काम कर रहे लोगों, प्रवासी दिहाड़िदार, रेहड़ी–फड़ी लगाने वाले और घरों में काम करने वाले प्रवासी लोगों के पहचान पत्रों की पुन: जांच की जाएगी।

अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार आजीविका कमाने के लिए प्रदेश के बाहर से आए रेहड़ी–फड़ी वालों के लिए अलग से स्थान चिन्हित करने के लिए भी विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहां पर सभी को किसी भी प्रदेश में जाकर काम करने की आजादी है।

अनिरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य सिंह ने मोहम्मद लतीफ, मौलवी शहजाद और वक्फ बोर्ड के सदस्य द्वारा विवादित ढांचे को स्वयं तोड़ने की पहल करने की सराहना करते हुए कहा कि इस निर्णय से समाज में आपसी भाईचारे की भावना को बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस कदम से शांति स्थापित करने और आपसी भाईचारे की दिशा में एक अद्भुत मिसाल कायम की गई है।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कोविड के समय बिना अनुमति के यह ढांचा कैसे बनाया गया इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तत्कालीन नगर निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भूमिका को कई सवाल खड़े होते हैं जिसकी आने वाले समय में जांच की जाएगी। उन्होंने स्थानीय लोगों से आग्रह किया कि जब तक आयुक्त न्यायालय अन्तिम निर्णय नहीं ले लेता तब तक सभी संयम बना कर रखें और कानून को अपने हाथों में लेने से बचें।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान हिमाचल प्रदेश धर्मान्तरण कानून को लागू करने वाला पहला राज्य बना था। प्रदेश सरकार लोगों की भावनाओं की कद्र करती है और यह भी अपेक्षा करती है कि राज्य के शांत वातावरण को किसी के बहकावे में आकर नहीं बिगड़ने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह विवाद मस्जिद के कानूनी और गैर कानूनी ढांचे को लेकर शुरू हुआ था लेकिन भाजपा नेताओं ने बीच में आकर इस पूरे विवाद को धार्मिक रूप दे दिया। उन्होंने कहा कि संजौली में आन्दोलन के दौरान कुछ लोगों ने पुलिस पर पत्थरों से हमला किया जिसके पश्चात् पुलिस को भीड़ नियंत्रित करने के लिए बल का प्रयोग करना है। इस बीच आन्दोलनकारी एवं पुलिस को चोटे भी आई जो कि खेदजनक है और हिमाचल की संस्कृति का हिस्सा नहीं है।

भाजपा मुस्लिम विरोधी नहीं है इसलिए पैसा दिया होगा:रणधीर

एक जगह मुख्यमंत्री सर्वदलीय बैठक बुला रहे है और दूसरी ओर उनके मंत्री प्रेस वार्ता कर भाजपा पर आरोप लगा रहे है

शिमला/शैल। भाजपा नेता एवं विधायक रणधीर शर्मा

ने सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भाग लिया। रणधीर शर्मा को इस बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने जाने के लिए अधिकृत किया था।

उन्होंने बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा की हाल ही में संजौली विवाद को लेकर समाज आन्दोलित हुआ और एक जन आन्दोलन खड़ा हुआ जिस पर आज विस्तृत चर्चा हुई।

उन्होंने कहा की जिस भवन को लेकर विवाद खड़ा हुआ है जब वह सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बना है तो इस भवन को सरकार द्वारा तुरन्त सील करना चाहिए और सरकार को अपने नियंत्रण में लेना चाहिए। इस भवन में कोई भी गतिविधि न हो उसको सुनिश्चित करना चाहिए। इस पर मुख्यमंत्री ने लीगल एक्सपर्ट की राय लेकर कार्य करने को कहा।

उन्होंने कहा की बाहर से को लोग हिमाचल में आ रहे है उनकी वेरिफिकेशन और आइडेंटीफिकेशन होना आवश्यक है। अगर वह हिमाचल में कोई काम कर रहे है तो उनके लाइसेंस बनने चाहिए, सरकार को इस पर गंभीरता से काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया की वह विधानसभा अध्यक्ष से बात कर दोनों दलों को संयुक्त समिति बनाकर इस विषय पर जल्द नीति लाएंगे। रणधीर ने कहा की यह समस्या शिमला की नहीं बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश की है।

रणधीर से कहा की एक जगह मुख्यमंत्री सर्वदलीय बैठक बुला रहे है और दूसरी ओर उनके मंत्री प्रेस वार्ता का भाजपा पर आरोप लगा रहे है। वैसे तो मंदिर और मस्जिद के लिए कोई सरकार पैसा नहीं दे सकती पर आस पास की सराय के लिए पैसा देना गलत नहीं है।

रणधीर ने कहा की भाजपा मुस्लिम विरोधी नहीं है इसलिए पैसा दिया होगा।

उन्होंने सरकार से आग्रह किया की इस विवाद को लेकर कांग्रेस सरकार को ही समाधान निकालना है और यह समाधान जल्द निकालना चाहिए।